दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुलों की मियाद

1943. **श्री लक्खीराम अग्रवाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेल मार्ग पर पड़ने वाली नदियों और नालों पर बने कुछ रेल-पुलों की मियाद पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुलों की संख्या कितनी है और उन पुलों को उनकी मियाद समाप्त हो जाने के पश्चात् भी उपयोग में लाये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Extension of trains upto Dibrugarh

1944. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to introduce new train(s) and extend running of existing trains upto Tinsukia only and not upto Dibrugarh in 1996-97 after completion of gauge conversion work between Dimapur and Dibrugarh; if so, the reasons therefor;

(b) if reply to Part (a) above be in the affirmative, what is the justification for gauge conversion upto Dibrugarh; and

(c) whether Government propose to review its decision and introduce/extend new/existing trains upto Dibrugarh; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग का प्रभाव

1945. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा रसायनों और उर्वरकों हेतु राज-सहायता में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ख) क्या यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप भूमि की उर्वरता उत्तरोत्तर कम होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई आधिकारिक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) दिनांक 6.7.1996 से फास्फेटिक तथा पोटेशिक उर्वरकों पर राजसहायता इस प्रकार से बढ़ाई गई है:

(रूपए प्रति टन)

डी०ए०पी० (स्वदेशी)	1000	3000
डी०ए०पी० (आयातित)	—	1500
एम०ओ०पी०	1000	1500
सिंगल सुपर फास्फेट (एस०एस०पी०)	340	500
मिश्रित (काम्पलेक्स)	435-999	1304-2640

एन०पी०के० के अनुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से इन उर्वरकों के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया है।

(ख) से (घ) एन०पी०के० उर्वरकों के प्रयोग में असन्तुलन निरन्तर रूप से मृदा की मात्रा में सूक्ष्म-पोषक तत्वों को दूर करता है, जो कि मृदा के उपजाऊपन पर प्रभाव डालता है। दीर्घावधि वाले उर्वरक परीक्षणों पर अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना के तहत किए गए कई प्रयोगों ने स्पष्ट रूप से इन तथ्यों का संकेत किया कि रासायनिक उर्वरकों व आर्गेनिकों का सन्तुलित एवं समेकित प्रयोग निरन्तर रूप से वृद्धित फसल उत्पादकता के लिए आवश्यक है। तथापि, कोई भी सरकारी अध्ययन संचालित नहीं किया गया है।

ग्रामीण शिक्षा समितियां

1946. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में ग्रामीण शिक्षा समितियों की स्थापना किये जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण शिक्षा के प्रसार के लक्ष्य को कहां तक पूरा किया गया है;

(ग) इन समितियों का स्वरूप क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण शिक्षा समितियों हेतु केन्द्रीय बजट में से कितनी वित्तीय सहायता राशि का प्रावधान किया जा रहा है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु क्या अन्य नए प्रबंध किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (ङ) 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा उन विषयों में एक है जिसे पंचायती राज निकायों को अन्तरित किया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समितियों की ग्राम स्तर की शिक्षा की विकेन्द्रीकृत आयोजना और प्रबंधन को सुकर बनाने वाले मुख्य कारक के रूप में परिकल्पना की गई है। हालांकि ग्राम शिक्षा समितियों की वास्तविक संरचना राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न है फिर भी ग्राम शिक्षा समिति की परिकल्पना इस रूप में की गई है कि इसमें पंचायतों के चुने हुए पदाधिकारियों, ग्राम प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक, अभिभावकों तथा कमजोर वर्गों के प्रतिनिधियों सहित विस्तृत आधार पर प्रतिनिधित्व हो।

हालांकि केन्द्रीय बजट में ग्राम शिक्षा समितियों के लिए कोई विशिष्ट धनराशि अलग से नहीं रखी गई है, तथापि वित्त आयोग द्वारा निधि संबंधी राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक शुरू की गई एक प्रमुख पहल को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि 1996-97 में अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके।

राजीव गांधी शैक्षिक मिशन

1947. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी शैक्षिक मिशन (राजीव गांधी एजुकेशनल मिशन) एक सरकारी योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश सरकार के शालेय शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक राज्य स्तरीय सवायत्त सोसाइटी है।

(ख) यह मिशन निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत है:—

1. मध्य प्रदेश में 15-35 के आयुवर्ग में लोगों के लिए साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

2. 6—14 वर्षों के आयुवर्ग में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशन मध्य प्रदेश राज्य में बाहरी सहायता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नामक शिक्षा संबंधी एक नई पहल का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके मुख्य संघटक है—

नए शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों का निर्माण, नए विद्यालयों को खोलना, विद्यालयों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की व्यवस्था, शिक्षकों का प्रशिक्षण, वैकल्पिक विद्यालयों/गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को खोलना, प्राथमिक पूर्व विद्यालयों, आश्रम शालाओं को खोलना, पाठ्यचर्या संशोधन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़ करना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना, प्रखण्ड संसाधन तथा सामूहिक संसाधन केन्द्रों की स्थापना, इत्यादि।

Conversion of catchment areas into reserve forest

1948. SHRI ONWARD L. NONGTDU: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the catchment areas in the North-Eastern Region are being destroyed by Jhumming; and

(b) if so, whether Government propose to acquire and convert those areas into reserve forest; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (Capt. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir. According to State of Forests Report, 1993 there is a loss of 635 sq. km. forests/tree cover in North-Eastern Region, over the last assessment. Out of